RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 10 JANUARY TO 16 JANUARY 2024 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 09 ■ अंक 16 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

नौसेना की 'दृष्टि' से बचना नामुमकिन है... समंदर के लिए बनाया 'उड़ता योद्धा' Page 2

देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार 7वें हफ्ते रेकॉर्ड उछाल Page 3

डाटा : एआई आधारित उद्योगिक क्रांति 4.0 का सिरमौर Page 4

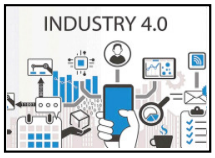

editoria!

आईसीयू भर्ती पर निर्देश

अस्पताल किसी मरीज को उसकी या उसके परिजन की सहमति के बिना । गहन चिकित्सा इकाई यानी इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) में भर्ती नहीं कर सकेंगे. उल्लेखनीय है कि आइसीयू किसी अस्पताल का वह वार्ड होता है, जहां गंभीर रूप से बीमार, ऑपरेशन के बाद निगरानी की जरूरत वाले तथा बड़े आघात वाले रोगियों को रखा जाता है, जिन्हें 24 घंटे निरीक्षण और उपचार की आवश्यकता होती है. भारत में पहली बार आइसीयू भर्ती को लेकर सरकार ने निर्देश जारी किया है. निर्देश में कहा गया है कि जब किसी रोगी के अंग काम नहीं कर रहे हों या उसकी तबियत बिगड़ने का अंदेशा हो, तभी आइसीयू में उसे रखने का निर्णय लिया जाना चाहिए. इसके अलावा, आइसीयू में बिस्तरों की उपलब्धता और मरीजों की स्थिति के आधार पर तैयार प्राथमिकता को भी ध्यान में रखने को कहा गया है. इन निर्देशों में आइसीयू से बीमार को छुट्टी देने के लिए भी मानदंडों का निर्धारण किया गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय के ये निर्देश 24 प्रतिष्ठित चिकित्सकों द्वारा तैयार किया है. भर्ती और छुट्टी के इन स्पष्ट निर्देशों से चिकित्सकों और मरीज के परिजनों के बीच भरोसा बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है. निर्देश में डॉक्टरों को सलाह दी गयी है कि जोखिम और फायदे के आकलन के बाद ही वे मरीज को आइसीयू में भर्ती करें और स्थिति में अपेक्षित सुधार के बाद सामान्य वार्ड में स्थानांतरित कर दें. ऐसी शिकायतें आती रही हैं कि अस्पताल अधिक पैसा कमाने के लिए मरीजों को मनमाने ढंग से भर्ती कर लेते हैं और जरूरत न होने के बाद भी उनकी छुट्टी नहीं करते. इससे मरीज पर आर्थिक बोझ पड़ता है और आइसीयू बिस्तरों की कमी भी हो जाती है. अब चिकित्सकों को परिजनों को स्पष्ट रूप से वे कारक बताने होंगे, जिनके चलते वे मरीज को आइसीयू में रखना चाहते हैं. उपचार में खर्च ऐसी चीज है, जो अस्पताल और रोगी के संबंधियों के बीच भरोसे को हानि पहुंचाती है. आइसीयू से मरीज को छुट्टी देने का निर्णय पूरी तरह रोगी की हालत पर निर्भर होना चाहिए, न कि परिवार की सहमति पर निर्देश में यह भी कहा गया है कि जहां तक संभव हो, ऐसे फैसले इस आधार पर नहीं लिये जाने चाहिए कि परिजनों के पास उपचार के लिए पैसे नहीं हैं, विशेषज्ञों की राय है कि देश में आइसीयू संसाधन सीमित हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल सोच-समझ कर किया जाना चाहिए. जब संसाधनों पर अधिक दबाव हो, तो महामारी और आपदा से त्रस्त लोगों को भी आइसीयू में भर्ती नहीं किया जाना चाहिए. चूंकि इन निर्देशों को प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने सोच-विचार कर तैयार किया है, तो आशा की जानी चाहिए कि अस्पताल इन पर ठीक से अमल करेंगे.

देश का Mutual Fund उद्योग पहली बार रु. 50 लाख करोड़ के पार

SIP ने तो कमाल ही कर दिया

नई दिल्ली। एजेंसी

देश के आर्थिक विकास की गाथा में एक और नया आयाम जुड़ गया। साल 2023 में देश के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कुल असेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 50 लाख करोड़ रुपये के भी पार पहुंच गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडस्ट्री का एयूएम रु. 50 लाख करोड़ के पार हो गया है। पिछले 10 साल में देखें तो इंडस्ट्री का एयूएम छह गुना बढ़ा है। साल 2013 में इंडस्ट्री का कुल एयूएम 8.25 लाख करोड़ रुपये था जो कि साल 2023 के अंत में बढ़ कर 50 लाख करोड़ रुपये से भी ऊपर पहुंच गया है। यह आंकड़े इंडस्ट्री की एपेक्स बॉडी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) ने जारी किया है।

पांच साल में म्युचूअल फंड निवेशक हुए दूने

एम्फी के चेयरमैन नवनीत मुणोत ने सोमवार को इंडस्ट्री के आंकड़े जारी किए। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 में देश के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का आंकड़ा 50 लाख करोड़ रुपये से भी ऊपर पहुंच गया जो कि ऐतिहासिक है। यह संभव हुआ नए भारत की पृष्ठभूमि तैयार करने से। पीएम मोदी ने कोविड के बाद देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए और देश में निवेश बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए। इसलिए ढेर सारे लोगों ने पहली बार म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश का रास्ता अपनाया। तभी तो पिछले पांच साल में म्यूचुअल फंड निवेशकों की संख्या दूनी से भी अधिक हो गई। दिसंबर 2018 में यह संख्या 1.91 करोड़ थी जो बढ़कर दिसंबर 2023 में 4.21 करोड़ हो गई है।

एएमएफआई के चीफ एक्जीक्यूटिव वेंकट चलसानी ने उद्योग की उपलब्धि पर अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए कहा, "जहां म्यूचुअल फंड उद्योग को पहले ?10 लाख करोड़ का एयूएम अर्जित करने में लगभग 50 साल लग गए थे, वहीं अंतिम ?10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ एक साल में अर्जित किए गए और ?40 लाख करोड़ से ?50 लाख करोड़ की राशि सिर्फ एक साल में जमा हो गई। इसके लिए एएमसी और नियामक सहित भारत में संपूर्ण म्यूचुअल फंड उद्योग ने एमएफ वितरकों के समर्थन से देश भर के निवेशकों तक पहुंचने के लिए केंद्रित प्रयास किए हैं।"

एक ही महीने में आए 17,610 करोड़

जैसे जैसे देश में फाइनेंसियल लिटरेसी बढ़ रही है, लोगों का निवेश म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बढ़ रहा है। हाल के दिनों में तो इस इंडस्ट्री में तेज बढ़ोतरी हो रही है। अब साल 2020 का ही उदाहरण देखिए। इस दौरान हर मंथली एसआईपी या सिप में एवरेज मंथली फ्लो करीब 8,000 करोड़ रुपये का था जो कि दिसंबर 2023 में बढ़ कर 17,610 करोड़ रुपये हो गया। यह ऑल टाइम हाई लेवल है। अकेले एसआईपी का क्यूमूलेटिव फ्लो 1,41,000 करोड़ रुपये के फ्लो को पार कर गया है। तभी तो दिसंबर 2023 तक सिप का एयूएम 10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

100 लाख करोड़ का आंकड़ा छूने को तैयार

एएमएफआई का मानना है कि उद्योग दशक के अंत तक रु. 100 लाख करोड़ एयूएम के आंकड़े को पार करने के लिए तैयार है। इस वृद्धि को हासिल करने के लिए निवेशक आधार को 4.21 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने की आवश्यकता होगी। एएमएफआई बाजार विस्तार की तीन अलग-अलग श्रेणियों का पालन करेगा जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होंगे - डिस्ट्रीब्यूशन आउटरीच, सरलीकरण और डिजिटलीकरण के माध्यम से मध्यम आय वाले परिवारों को शामिल करना और घरेलू बचत का और अधिक हिस्सा निवेश के लिए हासिल करना।

भारत-रूस के बीच अब कोई विवाद नहीं

जयशंकर ने लगाई गुहार तो ऐक्शन में पुतिन

मास्को/नई दिल्ली। एजेंसी

यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद कई मुद्दों से जूझ रहे भारत और रूस दोनों ही अपने सभी विवाद दूर करने में जुट गए हैं। भारत में रूस के राजदूत अलीपोव ने कहा है कि रूस और भारत दोनों व्यापार में घाटा, पेमेंट में आ रही दिक्कतों और बीमा से जुड़े मामले को सुलझाने पर काम कर रहे हैं। इससे पहले रूस के दौरे पर गए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस पूरे मामले को उठाया था। जयशंकर के पुतिन से गुहार लगाने के बाद अब रूस ऐक्शन में आ गया है। अलीपोव ने कहा कि अब दोनों ही देश एक-दूसरे को स्वीकार शर्तों को बनाने पर काम कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल किए जाने पर रूसी राजदूत ने कोई जवाब नहीं दिया। भारत और चीन के बीच विवाद पर रूसी राजदूत ने कहा कि हम आशा करते हैं कि भारत और चीन दोनों ही महान सभ्यताएं हैं जिनके अंदर राजनीतिक सूझबूझ है। ये दोनों ही देश सीमा विवाद पर आगे बढ़ने और संवेदनशील हितों पर आपसी सम्मान पर आधारित द्विपक्षीय रिश्तों को रास्ता हासिल कर लेंगे। बता दें कि भारत और चीन दोनों के बीच पिछले करीब साढ़े तीन साल से पूर्वी लद्दाख में तनाव अपने चरम पर है। यही नहीं गलवान हिंसा में दोनों ही देशों के कई सैनिकों की जान गई थी।

रूस ने पाकिस्तान की ब्रिक्स सदस्यता पर क्या कहा?

अलीपोव ने यह भी कहा कि भारत और रूस दोनों ही व्यापार को विविध बनाने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही भारत के साथ व्यापार में भारी असमानता को भी दूर करने पर रूस काम कर रहा है। भारत यूक्रेन युद्ध के बाद साल 2021 से रूस से तेल खरीद रहा है जिससे उसका व्यापार घाटा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक तरफ जहां रूस का निर्यात भारत को कई गुना बढ़ गया है, वहीं भारत से रूस को निर्यात में कोई खास बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। अलीपोव ने कहा कि हमारा इरादा इस व्यापार घाटे को कम करने पर है।

रूसी राजदूत ने भारतीय व्यापारियों को न्योता दिया कि वे रूस के बाजार का लाभ उठाएं जहां खूब संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि चुनौतिपूर्ण स्थितियों के बाद भी भारत और रूस के बीच रिश्ते अच्छे बने हुए हैं। आपसी हित और विश्वास पर आधारित ये रिश्ते आगे भी बढ़ते रहेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वहीं पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करने के सवाल पर रूस के राजदूत ने कहा, 'अभी हम उन देशों को शामिल करने की प्रक्रिया में हैं जिन्हें पिछले साल आमंत्रित किया गया था।' रूस इस समय ब्रिक्स का अध्यक्ष है और पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। पाकिस्तान को चीन की खुलकर मदद मिल रही है। वहीं भारत पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल किए जाने का कड़ा विरोध कर रहा है। इस वजह से रूस भारत बनाम चीन में फंसा हुआ नजर आ रहा है।

रूस से होड़ में सऊदी अरब ने किया ये फैसला, भारत को होगा बड़ा फायदा

नई दिल्ली। एजेंसी

सऊदी अरब के एशिया के दो बड़े खरीददार भारत और चीन तेल के लिए उस पर अपनी निर्भरता लगातार कम करते जा रहे हैं। ये देश अब रूस से तेल खरीद रहे हैं जो सऊदी के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है. ऐसे में सऊदी लगातार अपने तेल के दाम में कमी ला रहा है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको ने अपने फ्लैगशिप अरब लाइट कच्चे तेल की कीमतें एशिया के लिए घटा दी है। सऊदी ने अरब लाइट कच्चे तेल की कीमत पिछले 27 महीनों में सबसे कम कर दी है जिससे भारत को बड़ा फायदा होने वाला है। सऊदी अरब के इस कदम से भारत समेत एशियाई देशों को अब सस्ता तेल मिलेगा और कच्चे तेल के निर्यात की लागत में कमी आएगी।

अरामको ने फरवरी के लिए अपने कच्चे तेल की शिपमेंट में 2 डॉलर प्रति बैरल की कमी की है। इससे पहले दिसंबर के महीने में जनवरी के शिपमेंट के लिए अरामको ने 1.5 डॉलर प्रति बैरल की कटौती की घोषणा की थी। दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक सऊदी अरब ने एशिया समेत उत्तरी अमेरिका, उत्तर-पश्चिम यूरोपीय देशों के लिए भी अपने तेल की कीमत कम कर दी है।

तेल की कीमतें अचानक से कम क्यों करने लगा सऊदी अरब?

सऊदी अरब ओपेक प्लस देशों के साथ मिलकर लगातार तेल उत्पादन में कटौती कर रहा था ताकि तेल की कीमतें बढ़े लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी तेल की कीमतों में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। अमेरिका ने कई बार सऊदी अरब से तेल का उत्पादन बढ़ाने को कहा लेकिन जब सऊदी ने ऐसा नहीं किया तब अमेरिका ने खुद अपना तेल उत्पादन भारी पैमाने पर बढ़ा दिया।

अमेरिका के साथ-साथ गैर ओपेक देश ब्राजील और मैक्सिको ने भी अपना तेल उत्पादन बढ़ा दिया जिससे तेल बाजार में तेल की पर्याप्त उपलब्धता हो गई और तेल की कीमतें गिरने लगीं। सऊदी अरब के लिए एशिया एक बड़ा बाजार है। दुनिया के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता चीन और भारत उसका सबसे अधिक तेल खरीदते हैं। ऐसे में तेल बाजार में अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए सऊदी को तेल की कीमतों में कमी करनी पड़ रही है। सऊदी नहीं चाहता कि अमेरिका और ब्राजील जैसे देश उसके हिस्से का तेल बेचें।

रूस भी है एक बड़ा फैक्टर

यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों को देखते हुए रूस ने भारत और चीन को रियायती दरों पर तेल ऑफर किया। भारत युद्ध से पहले रूस से अपने कुल तेल खरीद का 1इ से भी कम तेल खरीदता था लेकिन जब रूस ने सस्ता तेल ऑफर किया तो भारत ने ताबड़तोड़ खरीद शुरू कर दी। आज आलम यह है कि रूस सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। चीन भी रूस से भारी मात्रा में तेल की खरीद कर रहा है। इसे देखते हुए सऊदी अरब अपने तेल की कीमतों में कमी ला रहा है ताकि उसके बड़े खरीददार रहे भारत और चीन सऊदी से तेल की खरीद बढ़ा दें।

सेंसेक्स 272 अंक चढ़ा, निफ्टी 21600 के पार हुआ बंद

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी देखने को मिली और सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। मिडकैप शेयरों में खरीदारी रही जबकि स्मॉलकैप पर दबाव देखने को मिला। मेटल, IT, बैंकिंग इंडेक्स बढ़त पर बंद हुआ जबकि एनर्जी, इंफ्रा, ऑटो इंडेक्स हरे निशान में बंद हुआ। PSE, FMCG, रियल्टी शेयरों पर दबाव रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 271.50 अंक यानी 0.38 फीसदी की बढ़त के साथ 71,657.71 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 73.85 अंक यानी 0.34 फीसदी की बढ़त के साथ 21618.70 के स्तर पर बंद हुआ।

नौसेना की 'दृष्टि' से बचना नामुमकिन है... समंदर के लिए बनाया 'उड़ता योद्धा'

राम एस. पाल

इंदौर। अडाणी ग्रुप की कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए ड्रोन स्वदेशी ड्रोन बनाया है। इस स्वदेशी ड्रोन का नाम ळैंइ दृष्टि-10 रखा गया है। ये स्टारलाइनर ड्रोन है, जिसे आज अडाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने भारतीय नौसेना को सौंप दिया। इस स्वदेशी ड्रोन के शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना का ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। स्वदेशी तकनीक पर आधारित ये ड्रोन काफी एडवांस है। बुधवार को हैदराबाद में फ्लैगऑफ कार्यक्रम में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने ड्रोन का अनावरण किया। ळैंइ दृष्टि-10 ड्रोन किस तरह से नौसेना की ताकत बढ़ाएगा आइए बताते हैं।

UAV दृष्टि-10 ड्रोन में क्या खूबियां?

UAV ड्रोन एडवांल इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोही (आईएसआर) प्लेटफॉर्म है। ये ड्रोन हैदराबाद से पोरबंदर के लिए उड़ान भरने के बाद नौसेना के समुद्री अभियानों में शामिल किया जाएगा। अडाणी ग्रुप के अनुसार, UAV दृष्टि-10 स्टारलाइनर 36 घंटे तक उड़ने में सक्षम है। ये स्वेदेशी ड्रोन एक बार में 450 किलोग्राम भार उठा सकता है। ये स्वदेशी ड्रोन कोए TANAG 4671 सर्टिफाइड है। दृष्टि-10 की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये किसी भी मौसम और स्थिति में उड़ान भर सकता है। इसे अलग और एक साथ दोनों तरह से उड़ने की मंजूरी दी गई है।

समुद्री निगरानी में मदद करेगा ड्रोन

हैदराबाद में फ्लैगऑफ कार्यक्रम में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने भारतीय नौसेना की जरूरतों के साथ अपने रोडमैप को बताया। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अडाणी ग्रुप की सराहना की। नौसेना प्रमुख ने कहा, 'यह घ्ईं टेक्नॉलजी और समुद्री वर्चस्व में आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अडाणी ग्रुप ने न केवल मैन्युफेक्चरिंग में बल्कि ड्रोन के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल में भी मदद की है। हमारे नौसैनिक अभियानों में दृष्टि-10 का एकीकरण हमारी क्षमताओं को बढ़ाएगा, समुद्री निगरानी में ये ड्रोन हमारी मदद करेगा।'

नौसेना की सेवा करने पर गर्व

अडानी एंटरप्राइजेज से जुड़े जीत अडानी ने हाल की भू-राजनीतिक घटनाओं के मद्देनजर

खुफिया, निगरानी और टोही प्लेटफार्मों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। उन्होंने प्रभावी सूचना प्रसार के लिए खुफिया तंत्र,बेहतर कम्युनिकेशन, ड्रोन जैसी मानव रहित तकनीक और साइबर टेक्नॉलजी की जरूरत पर जोर दिया। दिया। वहीं अडाणी ने कहा कि वह भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों को पूरा करने और भारत को वैश्विक निर्यातक के रूप में स्थान देने के लिए तीनों सेनाओं और सीमा पर तैनात सुरक्षाबलो के लिए खुफिया और निगरानी के लिए प्लेटफॉर्म के विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें भारतीय नौसेना की सेवा करने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने पर गर्व है'।

पेट्रोकेमिकल उद्योग ने किया ओमान एफटीए का विरोध, डील में हो सकती है देरी

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत थोड़ी लंबी खिंच सकती है क्योंकि भारतीय पेट्रोकेमिकल उत्पादकों ने समझौते में प्रस्तावित पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीइथाइलीन पर किसी भी गहरी शुल्क कटौती का विरोध किया है। प्लास्टिक के लिए प्रमुख कच्चे माल पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीइथाइलीन दोनों पर वर्तमान में 7.5इ का आयात कर (मूल सीमा शुल्क) लगता है। यह 18इ एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के अतिरिक्त है, जिसका उद्देश्य घरेलू उत्पादों पर लगने वाले जीएसटी की भरपाई करना है। घरेलू उद्योग का तर्क यह है कि ओमान अपने पेट्रोकेमिकल उत्पाद उद्योग को बड़ी मात्रा में कच्चे माल की सब्सिडी प्रदान करता है और इन पर शुल्क रियायतें ओमानी कंपनियों के लिए दोहरा लाभ होगा। वित्त वर्ष 23 में ओमान से 7.5 बिलियन डॉलर के कुल आयात में से 383 डॉलर पॉलीप्रोपाइलीन और एथिलीन पॉलिमर का था। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि वे इस मुद्दे पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में घरेलू खिलाड़ियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। रिलायंस भारत में पॉलीप्रोपाइलीन का सबसे बड़ा उत्पादक है जबकि हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स पॉलीथीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण खिलाड़ी इंडियन ऑयल, गेल (इंडिया) और अन्य राज्य संचालित तेल कंपनियां हैं। उपयोगकर्ता उद्योग, मुख्य रूप से प्लास्टिक निर्माताओं का कहना है कि शुल्क में कटौती से श्रम-प्रधान क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि कच्चे माल की लागत अंतिम माल का लगभग 60इ है। इससे पहले एक अधिकारी ने कहा था कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत जल्द ही खत्म हो सकती है और जनवरी के अंत तक हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। गति का कारण यह है कि यह समझौता उसी के समान है जिस पर भारत ने 2022 में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ हस्ताक्षर किए थे। पेट्रोकेमिकल में ओमान को दी जाने वाली शुल्क कटौती क्या हो सकती है, इस सवाल का जवाब भारत और के बीच सीईपीए में निहित है। संयुक्त अरब अमीरात।

पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीइथाइलीन दोनों में भारत ने 10 साल की अवधि में शुल्क को आधे से घटाकर 3.75इ करने की पेशकश की है। लंबी अवधि के लिए शुल्क में कटौती के अलावा, भारत ने इन उत्पादों की मात्रा पर कोटा भी लगाया है जिन्हें हर साल आयात किया जा सकता है। भारत-यूएई समझौते में समय बीतने के साथ टैरिफ रेट कोटा बढ़ता जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नवंबर से भारत और ओमान के बीच पहले ही दो दौर की बातचीत हो चुकी है, जहां अधिकांश अध्यायों या नीति क्षेत्रों के पाठ को अंतिम रूप दिया जा चुका है। भारत और ओमान के बीच पहले दौर की बातचीत 27-29 नवंबर के बीच नई दिल्ली में हुई थी. कुछ ही हफ्तों में भारतीय टीम इस महीने के मध्य में मस्कट गई। खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों में ओमान भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। जबकि ओमान का आर्थिक आकार और जनसंख्या सीईपीए से सीधे प्राप्त होने वाले लाभों को सीमित करती है, इसका वास्तविक मूल्य महत्वपूर्ण महत्व के क्षेत्र में आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने में निहित है।

भारत की ₹1.4 बिलियन की तुलना में ओमान की जनसंख्या 5 मिलियन है। भारत की 3.5 ट्रिलियन डॉलर की तुलना में ओमान की अर्थव्यवस्था 115 बिलियन डॉलर है।

टैक्स फ्री हो सकती है 7.5 लाख रुपये तक की कमाई, बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दे सकती है मोदी सरकार

नई दिल्ली। एजेंसी

एक फरवरी को पेश वाले अंतरिम बजट में नई कर व्यवस्था के तहत कर मौजूदा कर छूट को सात लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये किया जा सकता है। इस बदलाव के लिए वित्त विधेयक पेश किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दे सकती है। एक फरवरी को पेश वाले अंतरिम बजट में नई कर व्यवस्था के तहत कर मौजूदा टैक्स छूट को सात लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस बदलाव के लिए वित्त विधेयक पेश किया जा सकता है। मामले से जुड़े दो अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सरकार यह फैसला लेती है तो करदाताओं को नई कर व्यवस्था में आठ लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस छूट में 50 हजार रुपये की मानक कटौती भी शामिल है। सरकार ने 2023 के बजट में नई कर व्यवस्था के तहत छूट को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये किया था।

मानक कटौती को किया था शामिल

गौरतलब है कि सरकार ने बजट 2023 में नई कर व्यवस्था में कई बदलाव करते हुए राहत दी थी। इसके मुताबिक, पहले नई कर व्यवस्था में किसी भी तरह के निवेश या कटौती का दावा नहीं किया जा सकता था, लेकिन बजट में इसमें मानक कटौती को शामिल कर लिया गया है। इसके तहत, करदाताओं को 50,000 रुपये तक की कर कटौती दी जाती है। वहीं, पेंशनधारियों को इस व्यवस्था के तहत 15,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है।

Tax Limit बढ़ाई थी

इसके अलावा नई व्यस्था के कर स्लैब में भी बदलाव किया गया था। इसके तहत मूल छूट सीमा को पहले के 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया था। रिकॉर्ड ध्ऊँ दाखिल हुए

आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31 दिसंबर तक रिकॉर्ड 8.18 करोड़ आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए गए थे। यह 2022-23 में इसी अवधि में दाखिल किए गए 7.51 करोड़ आईटीआर से 9 प्रतिशत अधिक था।

टैक्स रेवेन्यू 14.7 प्रतिशत बढ़ा

सरकार अपना कर संग्रह बढ़ाने पर जोर दे रही है। पिछले साल अप्रैल से नवंबर की अवधि में, कर राजस्व 14.7 प्रतिशत बढ़ा, जो प्रत्यक्ष कर के लिए 10.5 प्रतिशत और अप्रत्यक्ष कर टैक्स के लिए 10.45 प्रतिशत के बजट अनुमान से अधिक है। विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि सरकार को अधिक कर राहत पर विचार करना चाहिए।

ITR फाइल करने वालों की संख्या करीब 4 गुना हुई

100 करोड़ से अधिक कमाने वालों की कमाई घटी

नई दिल्ली। एजेंसी

पिछले हफ्ते शुक्रवार को भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में कमाई और इनकम टैक्स से जुड़ी कई बड़ी बातें सामने आई हैं। वित्त वर्ष 2013-14 में 23 ऐसे लोग थे, जिन्होंने 100 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की थी। उनकी कुल कमाई 29,290 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2021 में 100 करोड़ रुपये से अधिक कमाई करने वाले लोगों की संख्या 136 हो गई है। हालांकि, उनकी टोटल कमाई में अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी हुई है और यह 34,301 करोड़ रुपये रही।

अगर इन आंकड़ों के संदर्भ में देखा जाए तो 100 करोड़ रुपये से अधिक की कमाने वालों की कमाई में कमी देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2014 में 100 करोड़ रुपये से अधिक कमाने वाले 23 लोगों की कमाई पूरे वित्त वर्ष की कुल कमाई में हिस्सेदारी 1.64 फीसदी थी। वहीं दूसरी ओर, भले ही 2021 में 100 करोड़ से अधिक कमाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, लेकिन कुल कमाई में उनकी हिस्सेदारी घटकर 0.77 फीसदी रह गई है।

करदाताओं की संख्या बढ़ी

ताजा डाटा के मुताबिक 5-10 लाख रुपये कमाने वाले करदाताओं की तरफ से आईटीआर फाइल करने की संख्या बढ़ी है। 2023-14 से अगर 2021-22 की तुलना करें तो यह 295 फीसदी बढ़ी है यानी करीब 4 गुना हो गई है। 10 लाख से 25 लाख रुपये के बीच कमाने वालों की तरफ से आईटीआर फाइल करने की संख्या 291 फीसदी बढ़ गई है। AY22 में 70 मिलियन आईटीआर फाइल हुए थे, जो AY23 में बढ़कर 74 मिलियन हो गए और AY24 में 31 दिसंबर 2023 तक यह संख्या 82 मिलियन पर पहुंच चुकी है।

आय में असमानता घटी

इनकम में असमानता निकालने के लिए उग्हग्र ण्दग्मिहू का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अनुसार AY15 (FY14) से AY23 (FY22) के बीच आय में असमानता 0.472 से घटकर 0.402 पर आ चुकी है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 36.3 फीसदी टैक्सपेयर ऐसे हैं, जो लोअर इनकम (3.5 लाख रुपये से कम) से हायर इनकम में गए हैं. एक बड़ा आंकड़ा ये भी सामने आया है कि 15 फीसदी करदाताएं महिलाएं हैं।

UPI पेमेंट का नया नियम लागू, ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को मिलेगा बड़ा फायदा

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

एनपीसीआई ने रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद यूपीआई पेमेंट लिमिट 5 लाख रुपये कर दी है। इससे मेडिकल और एजूकेशन सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। नया नियम 10 जनवरी 2024 से लागू होगा। एनपीसीआई ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को एडवाइजरी जारी की है। सरकार को ये नियम लागू करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो आपको आज से बड़ा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने आरबीआई की मंजूरी के बाद यूपीआई पेमेंट लिमिट 5 लाख रुपये कर दी है। मतलब अब यूजर्स एक दिन में अधिकतम 5 लाख रुपये यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। बता दें कि यूपीआई पेमेंट लिमिट में छूट की मांग लंबे वक्त से की जा रही थी, जिसे आज से लागू कर दिया गया है।

किसे मिलेगा फायदा?

यूपीआई पेमेंट लिमिट 5 लाख का फायदा मेडिकल और एजूकेशन सेक्टर में मिलेगा। मतलब अगर आप बीमारी के दौरान अस्पताल में पेमेंट करते हैं, या फिर किसी एजूकेशन के लिए पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप एक दिन में 5 लाख रुपये यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। बता दें कि अभी तक यह लिमिट 1 लाख रुपये हुआ करती थी। मतलब यूजर्स एक दिन में 5 लाख रुपये यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे.

कब से लागू होगा नया नियम?

यूपीआई पेमेंट लिमिट 5 लाख रुपये करने का नियम आज यानी 10 जनवरी 2024 से लागू हो रहा है। एनपीसीआई ने बढ़ी हुई 5 लाख लिमिट को लागू करने के लिए बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को एडवाइजरी जारी कर दी है।

फोनपे, गूगल पे को बड़ा फायदा

भारत में लगातार यूपीआई पेमेंट में इजाफा हो रहा है। वही 5 लाख रुपये यूपीआई पेमेंट लिमिट होने के बाद इ्पदहाझ, उददुत ईंब, ईंब्ल्ल जैसे पेमेंट प्लेटफॉर्म यूजर्स को बड़ा फायदा मिलेगा। भारत में सबसे ज्यादा फोनपे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद गूगल पे और फिर तीसरे नंबर पर पेटीएम शामिल है।

देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार 7वें हफ्ते रेकॉर्ड उछाल

नई दिल्ली। एजेंसी

देश के विदेशी मुद्रा भंडार में रेकॉर्ड इजाफा हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 29 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 2.76 अरब डॉलर बढ़कर 623.2 अरब डॉलर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे पिछले सप्ताह में देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 4.47 अरब डॉलर बढ़कर 620.44 अरब डॉलर हो गया था। उल्लेखनीय है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार अक्टूबर, 2021 में 645 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया था। पिछले साल से वैश्विक गतिविधियों के कारण उत्पन्न दबाव के बीच केंद्रीय बैंक ने पूंजी भंडार का उपयोग बाजार में जरूरी हस्तक्षेप के लिए किया। इससे मुद्राभंडार प्रभावित हुआ।

क्या कहते हैं आंकड़े

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, 29 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में, विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख घटक, विदेशी

मुद्रा आस्तियां 1.87 अरब डॉलर बढ़कर 551.61 अरब डॉलर हो गया। डॉलर में अभिव्यक्त की जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियों में यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं में घट-बढ़ के प्रभावों को शामिल किया जाता है।

स्वर्ण भंडार

रिजर्व बैंक के अनुसार स्वर्ण भंडार का मूल्य 85.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 48.33 अरब डॉलर हो गया। विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 3.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.36 अरब डॉलर हो गया। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार आलोच्य सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास रखा देश का मुद्रा भंडार 20 लाख डॉलर घटकर 4.89 अरब डॉलर रहा।

Budget 2024: अगले वित्त वर्ष 10 फीसदी Nominal GDP ग्रोथ का हो सकता है अनुमान

नई दिल्ली। एजेंसी

वित्त वर्ष 2025 के लिए 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (Nominal GDP) की वृद्धि दर 10 से 10.5 फीसदी रखे जाने की संभावना है जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए 8.9 फीसदी नॉमिनल जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया, 'हम वित्त वर्ष 2024 के लिए जीडीपी आंकड़ों के पहले अग्रिम अनुमान का इंतजार कर रहे थे। हम अगले कुछ दिनों में वित्त वर्ष 2025 के लिए अंतरिम बजट में नॉमिनल जीडीपी वृद्धि के अनुमान को अंतिम रूप दे देंगे। आंकड़ों की गणना से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए नॉमिनल जीडीपी वृद्धि 10 से 10.5 फीसदी के दायरे में रह सकती है।'

नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान बाजार मूल्य पर की जाती है और इसका उपयोग राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा (revenue deficit) तथा ऋण-जीडीपी अनुपात (debt-to-GDP ratio) जैसे महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक संकेतकों की गणना के लिए आधार के तौर पर किया जाता है।

उच्च नॉमिनल जीडीपी अनुमान से वित्त मंत्री को राजकोषीय घाटा (fiscal deficit) कम दिखाने में आसानी होती है जबकि कम नॉमिनल जीडीपी वृद्धि का मतलब राजकोषीय घाटा बढ़ने की आंशका होती है। पिछले 10 वर्षों के बजट अनुमान का बिज़नेस स्टैंडर्ड ने विश्लेषण किया है जिससे पता चलता है कि बजट में 7 बार नॉमिनल जीडीपी वृद्धि का अनुमान ज्यादा लगाया गया जबकि तीन बार कम अनुमान लगाया गया।

क्रिसिल (Crisil) के मुख्य अर्थशास्त्री डीके जोशी ने कहा, 'वित्त वर्ष 2025 के लिए 10.5 फीसदी नॉमिनल जीडीपी वृद्धि का अनुमान महत्वाकांक्षी नहीं होगा क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति (WPI inflation) सकारात्मक हो गई है और हाल के दिनों में 10.5 फीसदी वृद्धि का रूझान दिखा है।'

अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और जिंसों के दाम में नरमी के कारण अक्टूबर 2022 तक थोक मुद्रास्फीति लगातार 7 महीने तक अपस्फीति के दायरे (deflationary territory) में रही थी। नवंबर में मुख्य रूप से सब्जियों के दामों में तेजी के कारण थोक मुद्रास्फीति सकारात्मक होकर 0.26 फीसदी रही।

वास्तवित जीडीपी (Real GDP) की गणना नॉमिनल जीडीपी से जीडीपी डिफ्लेटर को घटाकर की जाती है। जीडीपी डिफ्लेटर (GDP deflator) थोक मुद्रास्फीति और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दरों का भारित औसत (weighted average) है जिसमें थोक मुद्रास्फीति का भारांश ज्यादा होता है। चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति ऊंची बनी हुई है मगर थोक मुद्रास्फीति के कम रहने से वित्त वर्ष 2024 में नॉमिनल जीडीपी वृद्धि घटकर 8.9 फीसदी रहने का अनुमान है जबकि बजट में इसके 10.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया था।

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि अगले साल नॉमिनल जीडीपी वृद्धि करीब 10 फीसदी रह सकती है। उन्होंने कहा, 'वित्त वर्ष 2024 में कम अपस्फीतिकारक (low deflators) की वजह से वृद्धि नरम रही। बजट तैयार करते समय सामान्यीकरण और आधार प्रभाव इस आंकड़े को तार्किक ठहराएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वित्त वर्ष 2025 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.75 से 6.8 फीसदी रहेगी।'

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) ने अपनी हालिया रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि 10.6 फीसदी और वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.3 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि खुदरा मुद्रास्फीति में अगले साल नरमी आएगी मगर थोक मुद्रास्फीति में तेजी आ सकती है। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2025 में नॉमिनल जीडीपी वृद्धि बढ़कर 9.5 फीसदी पहुंच सकती है।

साल 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनेगा भारत वित्त मंत्री ने गिनाई खूबियां

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि भारत वित्त वर्ष 2027-28 तक पांच लाख करोड़ डॉलर से अधिक के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके साथ ही सीतारमण ने कहा कि रुढ़िवादी अनुमानों के हिसाब से भी भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2047 तक 30 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगा।सीतारमण ने यहां आयोजित वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ''संभव है कि हम वित्त वर्ष 2027-28 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे और हमारी जीडीपी उस समय तक पांच लाख करोड़ डॉलर से अधिक हो जाएगी। एक रुढ़िवादी अनुमान है कि वर्ष 2047 तक हमारी अर्थव्यवस्था कम-से- कम 30 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी।'

अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

इस समय भारत लगभग 3.4 लाख करोड़ डॉलर के जीडीपी के साथ दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी उससे आगे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष में 7.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है जबकि पिछले वित्त वर्ष में इसकी वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रही थी। इस मौके पर सीतारमण ने कहा कि भारत को वर्ष 2023 तक 23 वर्षों के दौरान 919 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मिला है।

बैंक खाते बढ़े

इसमें से 65 प्रतिशत यानी 595 अरब डॉलर एफडीआई नरेन्द्र मोदी सरकार के पिछले आठ-नौ वर्षों के कार्यकाल में आया है। उन्होंने वित्तीय समावेशन का जिक्र करते हुए कहा कि बैंक खाता रखने वाले लोगों की संख्या 50 करोड़ हो गई है जबकि 2014 में 15 करोड़ लोगों के पास ही बैंक खाते थे।

8 महीने... 29000 फर्जी कंपनियों का भंडाफोड़

फेक GST रजिस्ट्रेशन के खिलाफ सरकार की सख्ती का असर

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार की ओर से फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ ये अभियान बीते साल मई 2023 के मध्य में शुरू किया गया था। तब से लेकर दिसंबर महीने तक 29,273 फर्जी कंपनियों का पता लगाया गया और इन मामलों में कुल 121 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

सरकार के वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, जीएसटी अधिकारियों द्वारा बीते साल दिसंबर 2023 तक देश में 29,000 से ज्यादा फर्जी कंपनियों (Bogus Firms) का भंडाफोड़ किया गया। ये कंपनियां 44,015 करोड़ रुपये के फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम (ITC) में शामिल थीं। ये कंपनियां महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा समेत अन्य राज्यों में पकड़ी गईं।

29,273 फर्जी कंपनियों का हुआ खुलासा सरकार की ओर से फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन (Fake GST Registration) के खिलाफ चलाए गए अभियान का असर दिखाई दिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा बीते साल 2023 के आठ महीनों में इस संबंध में की गई कार्रवाई का डाटा पेश किया गया है, जिसके मुताबिक फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम के दावों में शामिल 29,273 कंपनियों का पता लगाया गया। ये जो आंकड़ा सरकार की ओर से पेश किया गया है ये दिसंबर महीने तक का है. साल की आखिरी तिमाही में भी 4000 से ज्यादा कंपनियां पकड़ी गईं।

सरकार के 4646 करोड़ रुपये बचे पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, Finance Ministry के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 4,153 फर्जी कंपनियों का पता चला। इसमें बताया गया है कि फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ जारी इस अभियान के चलते सराकर को 4,646 करोड़ रुपये का रेवेन्यू बचाने में मदद मिली है। सिर्फ बीते साल की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 4,153 फर्जी कंपनियों का पता लगाया गया था, इससे 1,317 करोड़ रुपये के राजस्व को बचाने में मदद मिली, जिसमें से 319 करोड़ रुपये की वसूली हुई और 997 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम (ष्ठ्रुण) को रोककर करके सुरक्षित किए गए।

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फेक कंपनियां पकड़ीं

अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में की गई कार्रवाई के दौरान जो फर्जी कंपनियां पकड़ी गई हैं, उनमें से ज्यादातर महाराष्ट्र में हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो 926 कंपनियां महाराष्ट्र में थीं। इसके बाद राजस्थान में 507, दिल्ली में 483 और हरियाणा में 424 कंपनियों के पास फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन था। वित्त मंत्रालय द्वारा फर्जी कंपनियों का खुलासा करने के साथ ही बताया गया है कि जीएसटी अधिकारियों ने इन मामलों में इस अवधि में 41 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इनमें 31 सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर्स द्वारा की गई हैं।

बीते साल मई में शुरू किया गया था अभियान

सरकार की ओर से फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ ये अभियान बीते साल मई 2023 के मध्य में शुरू किया गया था। तब से लेकर दिसंबर महीने तक पता लगाए गए मामलों में कुल 121 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हालांकि, वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं। रजिस्ट्रेशन के समय बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन की पायलट प्रोजेक्ट्स गुजरात और आंध्र प्रदेश समेत अन्य राज्यों में शुरू किए गए हैं।

अब चाइनीज 'स्क्रू' पर भी सरकार का चला हंटर, यहां जानिए पूरी बात

नई दिल्ली। एजेंसी

कभी देश में खिलौनों, बिजली के सामानों आदि पर चाइना का एक छत्र राज हुआ करता था। सरकार ने धीरे-धीरे इस पर ध्यान दिया। देशी उद्योग को बढ़ावा दिया। चाइन से इसके सस्ते इंपोर्ट पर प्रतिबंध (Import Ban) लगाया। इसका असर दिखने लगा। अब देश में खिलौने की पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो गई है। यह न सिर्फ देशी बाजार की मांग पूरी कर रहा है बल्कि इसका एक्सपोर्ट भी शुरू हो गया है। अब बारी स्क्रू (Screw) की है। जी हां, आपके घरों में दरवाजे-खिड़की से लेकर फर्नीचर और तमाम जगह इस्तेमाल होने वाला स्क्रू। सरकार ने चाइना एवं कुछ अन्य देशों से स्क्रू के सस्ते आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। उम्मीद की जा रही है कि इससे देशी इंडस्ट्री को तो बढ़ावा मिलेगा ही, इसकी डंपिंग से भी निजात मिल जाएगी।

क्या आया है सरकार का फैसला

केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम काम करने वाले डाइरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने इस आशय की अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के मुताबिक अब 129 रुपये प्रति किलो से कम कीमत वाले स्क्रू का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया है। पहले इस तरह के स्क्रू का आयात फ्री था। इस इसे रिस्ट्रिक्टेड श्रेणी में डाल दिया गया है।

क्या है इस फैसले का मकसद

बताया जाता है कि सस्ते स्क्रू के आयात पर प्रतिबंध लगाने का मकसद स्क्रू के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना है। अभी तक इसका इंपोर्ट फ्री था तो व्यापारी सस्ते में चाइना, ऑस्ट्रेलिया, बंगलादेश, ब्राजील, बेल्जियम आदि देशों से इसका आयात कर लेते थे। जब बाजार इंपोर्टेड सस्ते स्क्रू से पट जाता था तो घरेलू स्क्रू को कौन पूछता। इसलिए सरकार को ऐसा कदम उठना पड़ा।

किस तरह के स्क्रू पर प्रतिबंध

सरकार ने जो प्रतिबंधित उत्पादों की सूची जारी की है, उसमें कोच क्रू, मशीन स्क्रू, लकड़ी के स्क्रू, हुक स्क्रू और सेल्फ-टैपिंग स्क्रू शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि भारत ने साल 2022-23 के दौरान 82.7 करोड़ डॉलर मूल्य का और चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर तक 46.81 करोड़ डॉलर के स्क्रू, बोल्ट, नट, वॉशर और इसी तरह की वस्तुओं का आयात किया है।

डाटा : एआई आधारित उद्योगिक क्रांति 4.0 का सिरमौर

राजकुमार जैन
अग्रणी सूचना प्रोद्योगिकी व्यवसायी और स्वतंत्र लेखक

जब से मानव प्रजाति ने इस धरती पर कदम रखा है बदलाव ही स्थायी है और बदलाव से तालमेल बैठाना एक निरंतर प्रक्रिया है। आज अपने चारों ओर ध्यान से नजर दौड़ाने पर हम पाते हैं कि सब कुछ अप्रत्याशित तेज गति से बदल रहा है। हमारे पहनने वाले कपड़ों से लेकर हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, और यहां तक कि हम अपने साथीयों के साथ कैसे मिलते हैं, संवाद करते हैं, काम करते हैं और खेलते हैं, सब कुछ परिवर्तन के अचंभित कर देने वाले दौर से गुजर रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बदलाव की गति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हम वर्तमान में परिवर्तन के एक त्वरित दौर के बीच में हैं जिसे चौथी औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। पिछली तीन औद्योगिक क्रांतियों के कारक थे मशीनीकरण, विद्युतीकरण और कम्प्यूटरीकरण और अब यह चौथी औद्योगिक क्रांति स्वचालन और स्मार्ट सोच वाली

मशीनों यानि एआई के नाम है।

एआई या मशीन लर्निंग, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए डेटा या जानकारी पर निर्भर होता है क्योंकि एआई इस जानकारी का उपयोग निर्णय लेने के तरीके को 'सीखने' के लिए करता है। प्रशिक्षण के दौरान और उसके बाद एआई मॉडल को जितनी अधिक जानकारी मिलती है उसका प्रदर्शन वास्तविक दुनिया के वातावरण में उतना ही बेहतर होता जाता है। अपने एआई मॉडल को सबसे बेहतरीन बनाने के बढ़ते दबाव ने एआई अग्रणी प्रतिस्पर्धी कम्पनीयों के बीच अपने अपने मॉडल को अधिकतम संभव डाटा सेट्स पर प्रशिक्षित करने का जूनून पैदा कर दिया है। जिसके चलते अब दुनिया सॉफ्टवेयर से डेटा की ओर स्थानांतरित हो रही है क्योंकि डाटा ही वो नया तत्व है जो एआई प्रशिक्षण की जीवनरेखा है।

एआई को अगली औद्योगिक क्रांति 4.0 का जनक माना जा रहा है, लेकिन वो एक अलग कहानी है। इधर बड़ी तकनीकी कम्पनीयों, वित्तीय क्षेत्र के अग्रणी खिलाड़ियों और सरकारों के गठजोड़ ने एक नई डेटा संस्कृति आधारित अर्थव्यवस्था का रास्ता खोला है। जिसमें डेटा परिपक्वता का अपेक्षित स्तर विकसित करना प्रमुखता से शामिल है। इसका अर्थ यह समझना है कि किसी संगठन के लिए कौन सा डेटा उपलब्ध है, उसके साथ क्या किया जा सकता है, और उस डेटा का सार्थक उपयोग करने के लिए किन उपकरणों और प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता है। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात है पूरे संगठन में डेटा साक्षरता की संस्कृति का निर्माण करना। बोर्डरूम से लेकर फैक्ट्री तक, उत्पाद के परिवहन से लेकर रिटेल काउंटर तक, हर व्यक्ति और परिचालन क्षेत्र को डेटा का मूल्य, नवाचार और दक्षता को बढ़ावा देने की उसकी शक्ति और उसे संग्रहीत करने, भंडारण करने और उपयोग करने की सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में पता होना चाहिए।

आज की दुनिया में, कोई भी संगठन जो अधिक कुशल तरीके से काम करने में सक्षम होना चाहता है, उन्हें इस बारे में सोचने की जरूरत है कि वो डेटा का उपयोग कैसे कर सकते हैं। चाहे उनके पास ऑन-प्रिमाइसेस, निजी क्लाउड या सार्वजनिक क्लाउड ऐप्स हों, फिर भी एक कनेक्टेड एंटरप्राइज़ के रूप मे काम करने के लिए उनके पास इन विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त डेटा को एक साथ लाने की क्षमता होना आवश्यक है। आज की दुनिया मे सफल उद्यम वही होंगे जिन्होंने डेटा द्वारा संचालित व्यवसाय के नए मॉडल को अपनाने के लिए डिजिटल रूपांतरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक संसाधनों में निवेश किया है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संसार में, डेटा की बादशाहत से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह एआई की जीवन-ऊर्जा है, जो किसी भी एआई आधारित उद्यम के कार्यशील रहने और निरंतर विकास के लिए आवश्यक है। यदि एआई दिमाग है तो डाटा उसका दिल और आत्मा है, जिसकी गुणवत्ता उसकी सफलता और विफलता का निर्धारण करती है। हम एक ऐसे युग में आगे बढ़ रहे हैं, जहां एआई उद्योगों, अर्थव्यवस्थाओं और समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ऐसे में त्रुटिरहित, वैध और उच्च-गुणवत्ता वाले स्वीकार्य डेटा की आवश्यकता अनिवार्य रूप से तेजी से बढ़ रही है।

यूं तो एआई के विकास और विस्तार की सफलता को विफल या बाधित करने वाले कई कारक हैं जैसे नीतिगत कार्यकारी समर्थन और धन की कमी, खराब परियोजनाएं, सुरक्षा और नियामक जोखिम आदि। फिर भी, डेटा से संबंधित मुद्दे सभी उद्योगों और भौगोलिक क्षेत्रों में आ रही एआई चुनौतियों के शिखर पर बने हुए हैं। एआई को सफल और मूल्यवान साबित होने के लिए एक भरोसेमंद और उच्च गुणवत्ता वाले डेटा स्रोत की आवश्यकता होती है। अपनी इसी अनूठी ताकत के चलते डाटा आज वो ईंधन बन चुका है जो एआई को परिकल्पना से वास्तविकता में ढालता है। यह एक बेजान एआई सिस्टम में जान फूंक देता है, जिससे उन्हें सीखने, अनुकूलन करने और विकसित होने में मदद मिलती है। डेटा की गुणवत्ता और उपलब्धता एक उत्कृष्ट एआई सिस्टम को बना या बिगाड़ सकती है। किसी बेआवाज फिल्म की तरह डाटा के बगैर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एआई सिस्टम भी प्रोद्योगिकी की एक मनभावन लेकिन भावहीन और बेजान मूरत मात्र रह जाती है।

बुलेट ट्रेन दौड़ने का समय तय

रेल राज्यमंत्री ने बताया किन स्टेशनों के बीच दौड़ेगी?

नई दिल्ली। एजेंसी

देश की पहली बुलेट ट्रेन दौड़ने का समय तय हो गया है। अब लोगों को इस ट्रेन से सफर करने के लिए अधिक इंतजार नहीं करना होगा। रेल राज्यमंत्री ने स्वयं इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि गुजरात के किन स्टेशनों के बीच पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किमी लम्बे बुलेट ट्रेन लाइन का निर्माण हो रहा है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन के अनुसार पाइल टेस्टिंग का काम आधे से अधिक हो चुका है। इसके साथ निर्माणाधीन स्टेशनों का काम समय से पूरा कर लिया जाएगा। रेल राज्य मंत्री ने दर्शना जरदोश मंगलवार को बताया कि बुलेट ट्रेन का निर्माण काफी तेजी से चल रहा है। वर्ष 2026 में बिलिमोरा और सूरत के बीच ट्रेन का ट्रायल शुरू हो जाएगा. गुजरात, दादरा नगर हवेली और महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया गया है।

ट्रैक बेड बिछाने का काम शुरू

जापानी शिंकानसेन में उपयोग किए जाने वाले एमएएचएसआर कॉरिडोर ट्रैक सिस्टम के लिए पहले रीइंफोर्स्ड कंक्रीट (आरसी) ट्रैक बेड बिछाने का कार्य सूरत और आनंद में शुरू हो गया है। देश में पहली बार जे-स्लैब बैलास्टलेस ट्रैक सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। गुजरात के वलसाड में ज़ारोली गांव के पास स्थित 350 मीटर लंबी और 12.6 मीटर व्यास वाली पहली पहाड़ी सुरंग को केवल 10 महीनों में पूरा करना एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं 70 मीटर लंबा और 673 मीट्रिक टन वजनी पहला स्टील ब्रिज, सूरत, गुजरात में एनएच 53 पर बनाया गया है। पूरे रूट पर ऐसे 28 में से 16 पुलों निर्माण का निर्माण किया जा रहा है।

बुलेट ट्रेन पर एक नजर

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किमी लम्बी भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण कर रहा है, जिसका 352 किमी मार्ग गुजरात के नौ और महाराष्ट्र के तीन जिलों से होकर गुजरेगा। महाराष्ट्र में परियोजना की कुल लंबाई 156 किमी और नगर हवेली में 4 किमी है। परियोजना का कार्य इन सभी आठ जिलों में शुरू हो चुका है। इस कोरिडोर में 12 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। बुलेट ट्रेन की स्पीड 320 किमी प्रति घंटे की होगी और इसका डिजाइन 350 किमी प्रति घंटे के अनुसार होगी। मुंबई से अहमदाबाद दो घंटे में बुलेट ट्रेन पहुंचेगी।

बाजार में खनकने लगा 20 रुपये का सिक्का

देख कर चौंक रहे हैं लोग, जानें क्या है खासियत?

नई दिल्ली। एजेंसी

Reserve Bank of India ने 2020 में 20 रुपये का नया सिक्का जारी था। उसकी डिजाइनिंग छत्तीसगढ़ मुंगेली के रहने वाले स्वप्निल सोनी ने की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग (NID) अहमदाबाद के छात्र रहे स्वप्निल ने इस सिक्के को तब डिजाइन किया था, जब RBI ने इस सिक्के को डिजाइन करने के लिए एप्लीकेशन मांगी थी। भारतीय 20 रुपये का सिक्का (रू. 20) भारतीय रुपया का एक मूल्यवर्ग है। यह भारतीय रुपयों के सभी सिक्कों में सबसे अधिक मूल्यवर्ग का सिक्का है। वर्तमान रु. 20 का सिक्का 2020 से बाज़ार में प्रचलन के लिए जारी किया गया है, जबकि इस सिक्के का निमार्ण और ढलाई का कार्य 2019 से ही प्रारम्भ हो गया था। इस सिक्के का विमोचन मार्च 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोनावायरस के कारण देश में लगे लॉकडाउन के वजह से इसके

विमोचन की तारीख स्थानांतरित करके मई 2020 कर दी गई, जिसके फलस्वरूप मई 2020 में भारतीय रुपये के सिक्कों की नई श्रृंखला के साथ इसे जारी किया गया था।

इसका उपयोग 20 रुपये के नोट के समकक्ष किया जाता है। इन सिक्कों को सर्वप्रथम भारतीय रिज़र्व बैंक के मुम्बई में स्थित टकसाल में बनाया गया था, जिसके बाद मुंबई टकसाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को 20 रुपये के सिक्कों की कुल 10 लाख खेप सौंपी गयी। वर्तमान में मुम्बई के अलावा यह कोलकाता, नोएडा और हैदराबाद में स्थित टकसालों में भी बनाया जा रहा है।

20 रुपये के सिक्के की कुछ खास बातें

इसे कॉपर, जिंक, और निकल से बनाया गया है। इस सिक्के को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ डिज़ाइन, अहमदाबाद ने डिज़ाइन किया है। इस सिक्के के आगे वाले हिस्से पर अशोक स्तंभ और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। अशोक स्तंभ के दाईं तरफ़ भारत और बाईं तरफ़ इंडिया लिखा है। सिक्के के पिछले हिस्से पर हिन्दी और अंग्रेज़ी में 20 रुपये अंकित है। इस सिक्के पर ऐसे निशान हैं कि इसे नेत्रहीन लोग भी पहचान सकते हैं। आगे वाले हिस्से पर अनाज का निशान बना हुआ है।

प्रतीक्षा .....! शबरी बोली, यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो हे राम ! तुम यहाँ कहाँ से आते ... ?

राम गंभीर हुए और कहा कि भ्रम में न पड़ो माते! राम क्या केवल रावण का वध करने यहां आया है...? अरे रावण का वध तो मेरा अनुज लक्ष्मण भी कर सकता था। राम हजारों कोस चल कर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माते, ताकि हजारों वर्षों बाद जब कोई पाखण्डी भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे ।

तो इतिहास चिल्ला कर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी माँ ने मिल कर गढ़ा था।

जब कोई कपटी भारत की परम्पराओं पर उँगली उठाये तो । काल उसका गला पकड़ कर कहे कि नहीं। यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट करने के लिए चौदह वर्ष का वनवास स्वीकार करता है।

राम वन में बस इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाय तो उसमें अंकित हो कि सत्ता जब पैदल चल कर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे तभी वह रामराज्य है।

राम वन में इसलिए आया है, ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतिक्षाएँ अवश्य पूरी होती हैं। सबरी एकटक राम को निहारती रहीं।

डॉ. संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

राम ने फिर कहा कि राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता ! राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए, आदर्श की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए।

राम आया है ताकि विधर्मियों को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है द्य

राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक सूर्पणखाओं की नाक काटी जाए और खर-दूषणो का घमंड तोड़ा जाय।

और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी बूढ़ी शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। सबरी की आँखों में अश्रु भर आए, उसने बात बदलकर कहा— कन्द खाओगे पुत्र राम ... । राम मुस्कुराए बोले, बिना खाये जाऊंगा भी नहीं माँ...

बुध-शुक्र की युति से बनेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग, इन राशियों की पलटेगी किस्मत

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ इंदौर (म.प्र.)

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राशि परिवर्तन और युति का विशेष महत्व होता है। सभी ग्रह समय-समय पर एक से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों के जातकों के ऊपर रहता है। ग्रहों के राशि परिवर्तन और युति से कई तरह के शुभ और राजयोग का निर्माण होता है। जनवरी के महीने में दो प्रमुख ग्रहों के राशि परिवर्तन से बहुत ही शुभ राजयोग बनने जा रहा है। बुद्धि और वाणी के कारक ग्रह बुध अभी धनु राशि में हैं और 18 जनवरी को शुक्र ग्रह भी इसी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जिस कारण से लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बुध और शुक्र ग्रह की युति किसी राशि में होती है तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। इस योग के बनने से व्यक्ति के जीवन में सुख-शांति और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। बुध-शुक्र की युति से बनने वाला लक्ष्मी नारायण राजयोग कुछ राशि के जातकों को विशेष फलदायी रहने वाला साबित होगा। आइए जानते हैं इस युति से किन- किन राशि के जातकों को फायदा मिलेगा।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए धनु राशि में बुध-शुक्र की युति फायदा दिलाने वाला साबित होगा। नौकरी की तलाश करने वाले जातकों को नई नौकरी के कई प्रस्ताव मिल सकते हैं। अचानक से धन लाभ के संकेत हैं जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। शुक्र के प्रभाव से जहां भौतिक सुख-सुविधओं में वृद्धि देखने को मिलेगी वहीं बुध के शुभ प्रभाव से धन लाभ और मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी। परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी।

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों पर बुध-शुक्र की युति से बना लक्ष्मी नारायण राजयोग जीवन में खुशियां लाएगा। इस राशि के जातकों के लिए आने वाला समय बहुत ही मंगलकारी सिद्ध हो सकता है। कार्यक्षेत्र में सफलताएं हासिल होंगी। धन लाभ के बेहतरीन मौके हासिल होंगें। किसी को दिया गया उधार का धन आपको वापस मिलेगा। नौकरीपेशा जातकों के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा साबित होगा। जो लोग कोई व्यापार करते हैं उनको कोई अच्छी डील हासिल हो सकती है। संतान की तरफ से कोई शुभ सूतना मिल सकती है। इस राशि के जातकों के लिए शुक्र-बुध की युति किसी वरदान से कम नहीं है।

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए बुध-शुक्र की युति बहुत ही शुभ रहने वाली है। प्रेम के मामले में आपको अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। पार्टनर संग प्यार पहले के मुकाबले बढ़ सकता है। वहीं जीवनसाथी का अच्छा साथ मिलने से आप कोई बड़ा काम करने में कामयाब होंगे। मान-सम्मान और धन में वृद्धि की अच्छी संभावना है।

कुंभ राशि

लक्ष्मी नारायण राजयोग के निर्माण से कुंभ राशि के जातकों को सुखों की प्राप्ति होगी। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा जिससे आपके हर एक काम समय पर पूरे होंगे। नौकरीपेशा जातकों के वेतन में वृद्धि और प्रमोशन मिलने के योग हैं। व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा हासिल हो सकता है। भौतिक सुख-सुविधा में वृद्धि होगी।

पौष अमावस्या को शनि देव को प्रसन्न करने का बेहद उत्तम दिन

पं. राजेश वैष्णव
शनि उपासक ज्योतिष रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
98272 88490

पौष माह की कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि पौष अमावस्या कहलाती है. पौष अमावस्या कल यानी 11 जनवरी को है. धर्म और ज्योतिष में अमावस्या तिथि का बड़ा महत्व माना गया है. अमावस्या के दिन कई धार्मिक कार्य किये जाते हैं. इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध किए जाते हैं. पितृ दोष और कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए इस दिन उपवास भी रखा जाता है. पौष मास की अमावस्या के दिन कुछ खास काम करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है और उनके दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है.

पौष अमावस्या पर ऐसे करें शनि को प्रसन्न

अमावस्या का दिन शनि को प्रसन्न करने के लिए अति उत्तम माना जाता है. इस दिन पीपल के पेड़ का पूजन जरूर करना चाहिए. पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें और शनि के मंत्र 'ऊं शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें. पौष अमावस्या के दिन शनि मंदिर जरूर जाएं और शनिदेव की प्रतिमा पर सरसों का तेल या फिर तिल का तेल चढ़ाएं. इससे शनि के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है.

पौष मास को बहुत ही पुण्य फलदायी बताया गया है. पौष अमावस्या पर शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि स्तोत्र के साथ दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए. इस दिन हनुमान मंदिर जाने से भी शनि देव की कृपा प्राप्त होती है. इस दिन गरीबों को काले तिल या सरसों का तेल दान करें. इस दिन गलती से भी मांसाहारी भोजन या शराब का सेवन न करें. अगर आपके घर के आसपास कहीं शमी का पेड़ है तो उस पर जल, सरसों का तेल, काले तिल, गुड़ आदि चढ़ाकर उसकी पूजा करें. इस दिन शनि देव की छवि, यंत्र या मूर्ति के सामने शनि मंत्रों या चालीसा का जाप करना चाहिए.

पौष अमावस्या के दिन साबुत उड़द, लोहा, तेल, तिल के बीज, पुखराज रत्न और काले कपड़े का दान करना अति उत्तम रहता है. इस दिन शुभ शनि यंत्र घर में लाकर उसकी पूजा करने से जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है. शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना लाभदायक होता है. भगवान शंकर, शनिदेव के गुरु माने जाते हैं. इसलिए इस दिन भगवान शिव की आराधना करने और शिवलिंग पर तिल का जल अर्पित करने वालों को शनि देव का आशीर्वाद मिलता है.

रसोई में इन पौधों को रखने से होगा धन लाभ, घर से दूर होगी नकारात्मकता

आचार्य पं. संजय वर्मा
9826380407
ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ, इंदौर (म.प्र.)

वास्तु शास्त्र घर को समृद्ध कर सकता है, लेकिन आपको उसके नियमों को मानना पड़ेगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखने वाली हर वस्तु की अपनी ऊर्जा होती है। ऐसे में वास्तु के नियमों के हिसाब से ही वस्तुओं को उनकी सही दिशा में रखना चाहिए। घर की रसोई का भी अपना वास्तु होता है। घर की रसोई में वास्तु के अनुसार कुछ वस्तुओं के रखने भर से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इन वस्तुओं को रखने से आर्थिक लाभ होता है। यह वस्तु हैं पौधे। ज्योतिषाचार्य डॉ आरती दहिया के अनुसार आपको रसोई में कुछ विशेष पौधे रखने चाहिए। इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है।

एलोवेरा का पौधा

एलोवेरा के औषधीय गुण शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि एलोवेरा का पौधा वास्तु के लिए बहुत ही शुभ होता है। ऐसे में इसको हम अपनी रसोई में रख नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। इस पौधे को रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। एलोवेरा का पौधा आपके शरीर को भी कई तरह से फायदा पहुंचा सकता है। इस पौधे से अगर आप सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं, तो यह ध्यान रखें कि यह पौधा अच्छी रोशनी वाली जगह पर ही रखें।

तुलसी का पौधा

तुलसी का पौधा सनातन धरम बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर घर में तुलसी के पौधों को पूजा जाता है, लेकिन यह वास्तु के अनुसार भी काफी शुभ है। इस पौधे रसोई में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसको लगाने भर से काफी आर्थिक लाभ होता है। इस पौधे को किचन में लगाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भोजन शुद्ध शाकाहारी ही बने। रसोई में मांस-मदिरा नहीं बनना चाहिए। इस पौधे को रसोई के दक्षिण हिस्से में भूलकर भी न लगाएं। इस पौधे को उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में लगाएं।

टाटा मोटर्स ने परिवहन के भविष्य के लिए तैयार

इलेक्ट्रिक सपनों को हकीकत में बदल रहा है टाटा मोटर्स

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत में शहरीकरण और पर्यावरण के अनुकूल मोबिलिटी पर बढ़ते फोकस के कारण, परिवहन के स्वच्छ विकल्पों को अपनाना जरूरी हो गया है। देश इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन सेल-आधारित वाहनों की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में उत्सर्जन को कम करने के लिए एक फौरी समाधान की तत्काल जरूरत है। इसमें 'ट्रांजिशन फ्यूल' के रूप में मशहूर प्राकृतिक गैस एक अहम भूमिका निभाती है। भारत की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स प्राकृतिक गैस से चलने वाले वाहनों के विकास में सक्रियता से योगदान दे रही है। नए-नए आविष्?कार करने के लिए अपनी विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता का लाभ उठाते हुए, टाटा मोटर्स भारत में पर्यावरण को बचाने वाले परिवहन समाधानों का रुख करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

नीति आयोग की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक भारतीय सड़कों पर ट्रकों की संख्या चार गुना बढ़ जाएगी। इस रिपोर्ट में प्राकृतिक गैस-आधारित ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है। यह बदलाव वाणिज्यिक वाहन इंडस्ट्री में पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के मानकों को लागू करने के लिए जरूरी है। उत्सर्जन में कमी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए समर्पित भारत, सक्रिय रूप से कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (सीएनजी) के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है। सीएनजी किफायती होने के साथ ही भारत के कच्चे तेल के आयात बिल में भी कमी लाती है। नए-नए आविष्कार करने और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन समाधानों के लिए समर्पित, टाटा मोटर्स कमर्शियल वाहन सेक्टर में सीएनजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पर्यावरण हितैषी और कुशल परिवहन प्रणाली के लिए भारत की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप है। रिपोर्टों के अनुसार, मध्य प्रदेश में 200 से अधिक सीएनजी स्टेशन हैं, जो स्वच्छ ईंधन विकल्पों की व्यापक पहुंच में योगदान करते हैं।

भारत इस बदलाव में सहयोग करने के लिए अपने प्राकृतिक गैस बुनियादी ढांचे में निवेश कर रहा है। 2030 तक 17,000 सीएनजी स्टेशनों को चालू करने की योजना है। गैस ग्रिड, अतिरिक्त एलएनजी टर्मिनल और बायो-सीएनजी के लिए एसएटीएटी योजना जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का उद्देश्य प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को सभी तक पहुंचाना है। टैक्स क्रेडिट और सब्सिडी जैसे इंसेंटिव गैस आधारित वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करते हैं। नई प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण प्रणाली को सरकार की मंजूरी से पेट्रोल और डीजल की तुलना में सीएनजी और सस्ती हो जाएगी जो भारत में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

टाटा मोटर्स के ट्रक डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट और बिजनेस हेड श्री राजेश कौल ने कहा कि 'टाटा मोटर्स पर्यावरण की रक्षा करने वाले ईंधन का रुख करने के मामले में सबसे आगे है। सीएनजी से चलने वाले हमारे कमर्शियल वाहनों की रेंज और 2045 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन हासिल करने की प्रतिबद्धता के साथ हम सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स में भी नेतृत्व कर रहे हैं। ऑटो एक्सपो 2023 में प्राकृतिक गैस, बिजली और हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाले वाहनों का प्रदर्शन, परिवहन के भविष्य को आकार देने के लिए हमारे समर्पण को दर्शाता है। किफायती और पर्यावरण के अनुकूल होने तथा उपलब्धता के बढ़ने से जैसे-जैसे सीएनजी से चलने वाले वाहनों की मांग बढ़ रही है, हमें विश्वास है कि प्राकृतिक गैस इंडस्ट्री की शून्य-उत्सर्जन वाहनों की यात्रा में बड़ी भूमिका निभाएगी। हम एक साथ मिलकर हरियाली से भरपूर और ज्यादा बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं।'

टाटा स्टारबक्स ने हर तीन दिन में एक नए स्टोर की शुरुआत करने की योजना की घोषणा की

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

टाटा स्टारबक्स प्राइवेट लिमिटेड ने आज भारत में 2028 तक अपने स्टोरों की संख्या 1,000 तक पहुंचाने या हर तीन दिन में एक नए स्टोर की शुरुआत करने की योजना की घोषणा की। इससे पहले कंपनी ने नवंबर में लंबी अवधि की ट्रिपल शॉट रीइंवेन्शन स्ट्रैटेजी पेश की थी। इस रणनीति का पूरा ध्यान स्थानीय पार्टनर्स को रोजगार के लिए तैयार करने, बेहतर अनुभव के साथ ग्राहकों को सेवाएं देने वाले नए स्टोर्स की शुरुआत करने की ओर है। साथ ही कंपनी दुनिया भर में स्टारबक्स के ग्राहकों के बीच भारतीय मूल की कॉफी को बढ़ावा देना चाहती है।

इस हफ्ते भारत आए स्टारबक्स के चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर लक्ष्मण नरसिम्हन ने कहा पिछले 11 वर्षों के दौरान भारत पूरी दुनिया में स्टारबक्स के लिए सबसे तेजी से वृद्धि करते बाजारों में से एक बन गया है। भारत में मध्यम वर्ग का विस्तार हो रहा है, ऐसे में हमें गर्व है कि हम देश की समृद्ध विरासत का सम्मान करते हुए कॉफी संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं। अपने विश्वसनीय कारोबारी साझेदार, टाटा और हमारे ग्रीन एप्रन पार्टनर्स के साथ हम इन असीम संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम भारत में हर तीन दिन में एक स्टोर खोलने जा रहे हैं और सही मायनों में वैश्विक बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को गति देंगे।

टाटा स्टारबक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुशांत दास ने कहा हमने भारत में जो मजबूत नींव तैयार की है उसके दम पर हम वृद्धि के नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। यह अनोखा स्टारबक्स अनुभव तैयार करने की हमारी प्रतिबद्धता पर आधारित है जो ग्राहकों, समुदायों और साझेदारों को आगे बढ़ने में मदद करता है। चूंकि पार्टनर्स हमारे संगठन का मूल आधार हैं और भारत में हमारी सफलता को आकार दे रहे हैं, ऐसे में हम अपने पार्टनर्स के बेहतर भविष्य के लिए उचित निवेश करना जारी रखेंगे। तीसरे स्थान के बारे में नए सिरे से कल्पना करने के बारे में ध्यान केंद्रित करने और कॉफी के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका का विस्तार करने के साथ-साथ हम भारत में वृद्धि को गति देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

सुनील डिसूजा, सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कहा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और स्टारबक्स ने एक शानदार सफर तय किया है जिससे भारत की कॉफी संस्कृति और उच्च क्वालिटी की इंडियन एरेबिका कॉफी बीन्स के मूल में समाहित कला को बढ़ावा मिला है। चूंकि हम वृद्धि के नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं हम अपने ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को गहराई देने के लिए भारत की कॉफी संस्कृति को विकसित करना जारी रखेंगे और इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर अनोखी भारतीय पेशकशों को पहुंचाने के लिए इनोवेशन जारी रखेंगे।

भारत ने रोका निर्यात तो पाकिस्तानियों में प्याज के दाम 240 रुपये किलो

कराची। एजेंसी

पाकिस्तान में प्याज की कीमतों ने अवाम की आंखों में आंसू ला दिए हैं। पाकिस्तान में एक किलोग्राम प्याज की कीमत 240 रुपये तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में प्याज की बढ़ती कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं, क्योंकि भारत ने इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसका फायदा पाकिस्तान के थोक व्यापारी उठा रहे हैं। जब भारत ने 8 दिसंबर, 2023 को मार्च 2024 तक के लिए प्रतिबंध का ऐलान किया, तो पाकिस्तान के थोक व्यापारियों ने प्याज की जबरदस्त खरीदारी की। इससे पाकिस्तान में प्याज की कीमतें तुरंत ही 120 से 140 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 160 से 180 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गईं। तब से पाकिस्तान में प्याज की कीमतों में वृद्धि लगातार जारी है।

पाकिस्तान में क्यों बढ़ रही प्याज की कीमत

प्याज की बढ़ती कीमतों के कारण पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे उपभोक्ताओं को अब अन्य सब्जियों की तुलना में सबसे अधिक मांग वाली वस्तु के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। पाकिस्तान के खुदरा विक्रेताओं का कहना है कि भारी निर्यात मांग का लाभ उठाने के लिए निर्यातक ईरानी और काबुल प्याज की सीमित आवक को भी हटा रहे हैं। पाकिस्तान में प्याज के उत्पादन में भारी गिरावट देखी गई है। इसके कारण पिछले तीन महीनों में प्याज की स्थानीय कीमतें दोगुनी से अधिक हो गई हैं। इस बीच भारत ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध भी लगा दिया है।

भारत से सस्ता प्याज खरीदना चाहता है पाकिस्तान

पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि भारत जल्द से जल्द प्याज निर्यात से प्रतिबंध हटाए। पाकिस्तान को उम्मीद है कि भारतीय बाजार में प्याज की कम होती कीमतों के कारण इसके निर्यात पर लगा प्रतिबंध जल्द ही हट जाएगा। ऐसे में पाकिस्तानी निर्यातक इस अवसर का लाभ उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खुदरा विक्रेताओं ने कहा कि कीमतों में भारी बढ़ोतरी कई उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार सीमित मात्रा में सामान खरीदने के लिए मजबूर कर रही है क्योंकि वे अन्य सब्जियों की ऊंची दरों और बढ़ते खर्चों के कारण अपने बजट को बिगड़ने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

प्याज की कीमतें और ज्यादा बढ़ने का अनुमान

डॉन न्यूज से बात करते हुए फलाही अंजुमन थोक सब्जी बाजार सुपर हाईवे के अध्यक्ष हाजी शाहजहां ने कहा कि मध्यम गुणवत्ता वाली प्याज की थोक दरें 7,000 रुपये प्रति 40 किलोग्राम हैं, जबकि उच्च गुणवत्ता की कीमत 8,000 रुपये प्रति 40 किलोग्राम से अधिक है। उन्होंने दावा किया कि अरब देशों और दुबई में इसके आकार और मांग के कारण निर्यातक उच्च गुणवत्ता वाली खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की फसल लगभग खत्म हो चुकी है। इस कारण पाकिस्तान सिंध के विभिन्न इलाकों से आने वाली आपूर्ति पर निर्भर है, जिससे भी कीमतों पर दबाव बना हुआ है।

अब पैक्स के माध्यम से पीएम जन-औषधि केंद्रों में मिलने वाली सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाएँ

ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को भी उपलब्ध होंगी

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को 5 राज्यों के ईंएए को प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि केंद्र के संचालन के लिए स्टोर कोड वितरित करने के कार्यक्रम में यह स्पष्ट किया कि, 'अब ईंएए के माध्यम से इश जन-औषधि केंद्रों में मिलने वाली सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाएँ ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को भी उपलब्ध होंगी।'

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के कुशल मार्गदर्शन में PACS को बहुउद्देश्यीय बनाने का काम जोर-शोर से किया जा रहा है। सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने वाले शाह की देख-रेख में देश भर की 2,373 PACS को सस्ती दवा की दुकान यानी जन-औषधि केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है।

अंत्योदय की राजनीति करने वाले दिग्गज नेता अमित शाह के इस कदम से अब PACS के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों और किसानों को भी सस्ती दवाइयाँ मिल पाएंगी। इसके पहले इसका फायदा सिर्फ शहर के गरीबों को ही मिलता था, क्योंकि जन-औषधि केंद्र ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं।

बीते 10 साल में मोदी सरकार में फार्मेसी के क्षेत्र में ढेर सारे सुधार हुए हैं और आज पूरे विश्व में भारत फार्मा क्षेत्र में अग्रणी उत्पादक देश बन गया है। दुनिया भर को दवाएँ भेजने वाले भारत में 60 करोड़ की आबादी महंगी दवाएँ खरीद ही नहीं पाते थे। लेकिन अमृतकाल में जेनरिक दवाओं की व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन कर भारतीय जन-औषधि केंद्र के माध्यम से 60 करोड़ गरीबों तक दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आज ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। मोदी जी के 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र को साकार करने की दिशा में दिन-रात जुटे शाह की नीतियों के तहत अब सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से सुदूर गाँवों तक जन-औषधि केंद्रों की पहुँच बढ़ रही है।

लॉरिआल इंडिया के छात्रवृत्ति कार्यक्रम 'फॉर यंग विमेन इन सांइस' के लिए आवेदन आमंत्रित

एसटीईएम स्ट्रीम में स्नातक करने पर शैक्षणिक खर्च के लिए छात्रवृत्ति

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

लॉरिआल इंडिया ने अपने छात्रवृत्ति कार्यक्रम 'फॉर यंग विमेन इन साइंस' (एफवाईडब्ल्यूआईएस) 2023 के नवीनतम संस्करण की घोषणा की जोकि एक राष्ट्रव्यापी योग्यता पर आधारित छात्रवृत्ति कार्यक्रम है तथा यह योजना उन लड़कियों को स्नातक स्तर पर पढाई के लिए मंच प्रदान करती है जो विज्ञान में रुचि रखती हैं। लॉरिआल इंडिया ने अपने इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित करने शुरू कर दिए हैं जिनमें से सफल उम्मीदवारों को उनके पढ़ाई लिखाई से संबंधित खर्चों के लिए ढाई लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाएगी। यह छात्रवृत्ति योजना अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम 'लॉरिआल यूनेस्को फॉर विमेन इन साइंस' का एक विस्तार है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान में पढ़ाई करके उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता एवं जरूरी समर्थन प्रदान करना है।

यह कार्यक्रम भारत में सन 2003 में स्थापित किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से वंचित वर्ग की युवा महिलाएं अपनी पसंद के किसी भी प्रतिष्ठित एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में स्नातक स्तर पर विज्ञान की पढ़ाई कर सकती हैं। इस कार्यक्रम के तहत स्नातक स्तर पर विज्ञान की पढ़ाई के लिए कई क्षेत्र उपलब्ध हैं जिनमें प्योर साइंसेज, अप्लाइड साइंसेज, इंजीनियरिंग तथा मेडिसिन आदि शामिल हैं।

लॉरिआल इंडिया के कॉरपोरेट अफेयर्स एंड एंगेजमेंट के डायरेक्टर कृष्णा विलासिनी भारद्वाज ने कहा, 'लॉरिआल में, हम मानते हैं कि विज्ञान ही उन्नति की नींव है। जबकि यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स (यूआईएस) के आंकड़ों के अनुसार, एसटीईएम में महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कई कोशिश करी गईं, लेकिन दुनिया के केवल 33.3ऱ शोधकर्ता महिलाएं हैं। इस अंतर को पाटने के लिए, लॉरिआल ने 'फॉर यंग विमेन इन सांइस विज्ञान' छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत की, ताकि उन्हें वित्तीय सहायता देकर होनहार लड़कियों के लिए विभिन्न वैज्ञानिक विषयों को आगे बढ़ाने के रास्ते तैयार किए जा सकें।

पंप इनोवेशन में शक्ति पम्पस का 10वां पेटेंट

पीथमपुर। आईपीटी नेटवर्क

एनर्जी एफिशिएंट पंप्स और मोटर्स निर्माण की अग्रणी कंपनी शक्ति पंप्स (इंडिया) लिमिटेड को 'अ सर्फेस हेलिकल पंप कंस्ट्रक्शन विथ कोलिनियर फ्लो' के आविष्कार के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है। पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार ने 1970 के पेटेंट अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करते हुए, शक्ति पंप्स को यह पेटेंट प्रदान किया है। यह पेटेंट 20 वर्षों की अवधि के लिए वैध है और यह शक्ति पम्पस् का दसवां पेटेंट है।

शक्ति पंप्स का यह इनोवेशन आरओ झिल्ली में रुकावट आने पर भी लगातार जल प्रवाह को जारी रखता है, इस इनोवेशन के साथ शक्ति पंप्स की रिसर्च टीम ने सेंट्रीफ्युगल पम्पस् में अक्सर होने वाली समस्या का समाधान कर दिया है। इसकी बेहतरीन डिजाइन एफिशिएंसी को बढ़ाती है। बार बार झिल्ली बदलने की जरूरत को कम करके रखरखाव की लागत कम करती है और आरओ इंडस्ट्री को एक बेहतरीन आर्थिक समाधान देती है। पंप की एनर्जी एफिशिएंसी न केवल लागत को घटाती है बल्कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में भी योगदान करती है, जिससे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गोल्स पूरा करने में मदद मिलती है। शक्ति पंप्स का यह पेटेंट फ्लूइड टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसने समस्या का ठोस समाधान दिया है और इस इंडस्ट्री के अग्रणी इनोवेटर के रूप में कंपनी की स्थिति को और भी मजबूत किया है।

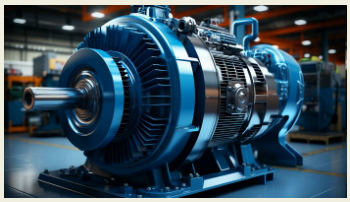

शक्ति पंप्स के चेयरमैन श्री दिनेश पाटीदार जी ने नई पेटेंट टेक्नोलॉजी के बारे में कहा,'हमारे पंप की शानदार एफिशिएंसी बिजली की खपत को काफी कम करती है, जिससे आरओ इंडस्ट्री को सीधे लाभ होता है और उनका रेवेन्यु बढ़ता है। बिजली की खपत में यह कमी से कार्बन फुटप्रिंट घटाने में भी मदद मिलती है, जो पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। भारत का लक्ष्य अधिक से अधिक एनर्जी एफिशिएंट बनने और एक इकोफ्रेंडली , सस्टेनेबल फ्यूचर का निर्माण करना है, हमें गर्व है कि हमारी नई तकनीक से हम अपने देश को ये लक्ष्य हासिल करने में मदद कर रहे हैं।'

बिड़ला सेलूलोज़ की खरच यूनिट ने सफलतापूर्वक हासिल किया ईयू बैट

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

गुजरात के खरच प्लांट में बिड़ला सेलूलोज़ ने सफलतापूर्वक एग्जॉस्ट गैसों से सीएपी (कार्बन-डाइसल्फ़ाइड एड्सॉर्प्शन प्लांट) CS2 रिकवरी सिस्टम को चालू कर और ईयू बैट का दर्जा हासिल कर लिया है। CS2 और H2ए (हाइड्रोजन सल्फाइड) के उत्सर्जन को घटाने के लिए क्लोज्ड-लूप तकनीकों का उपयोग किया गया है, जिसमें CS2 को रिकवर करना और H2ए से सल्फर के तत्व को शामिल किया गया है। 90-95 प्रतिशत सल्फर को रिकवर करने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। इस नई उपलब्धि को विस्कोस फाइबर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ईयू बैट बीआरईएफ में निर्धारित सभी मापदंडों के लिए ब्लूविन लिमिटेड, यूनाइटेड किंगडम द्वारा किए गए एक स्वतंत्र मूल्यांकन से आगे पास किया गया था। ग्रासिम इंडस्ट्रीज के एमडी और बिड़ला सेलूलोज़ के बिजनेस डायरेक्टर श्री एच के अग्रवाल ने कहा, यह ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और एमएमसीएफ इंडस्ट्री में सस्टेनेबल प्रैक्टिस के लिए ग्लोबल लीडरशिप हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

दुनिया में सबसे बड़े वीएसएफ उत्पादक केंद्रों में से एक बिड़ला सेल्यूलोज का विलायत प्लांट पहले से ही ईयू बीएटी के हिसाब से बनी साईट है, जो फाइबर उत्पादन के लिए सल्फर रिकवरी और जल खपत जैसे कई मापदंडों में वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है। बिरला सेल्यूलोज़ को हाल ही में जारी कैनोपी की हॉट बटन रिपोर्ट 2023 में अपने सस्टेनेबल फोरेस्ट्री प्रेक्टिस और नेक्स्टजेन सॉल्यूशन में इनोवेशन के लिए क्ष1 स्थान दिया गया है, और लगातार चौथे वर्ष इसे 'डार्क ग्रीन शर्ट' की सर्वोच्च रेटिंग प्राप्त हुई।

ज़ोमैटो ने इंदौर में 'डिलीवरी पार्टनर्स डे' मनाया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

'डिलीवरी पार्टनर्स डे' के अवसर पर ज़ोमैटो अपने डिलीवरी पार्टनर्स की असाधारण सेवा के सम्मान में उन्हें पुरस्कार वितरित करता है। ज़ोमैटो, भारत के फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी प्लेटफॉर्म, ने हाल ही में इंदौर में अपना 'डिलीवरी पार्टनर्स डे' मनाया। इस कार्यक्रम का आयोजन 5 एलीमेंट्स, बिचौली मर्दाना, इंदौर में किया गया और इसके स्पॉन्सर 5 एलीमेंट्स थे। यहाँ मौजूद ज़ोमैटो के 180 डिलीवरी पार्टनर्स में से 120 को पुरस्कार वितरित किए गए। कंपनी अपने 'डिलीवरी पार्टनर्स डे' कार्यक्रमों द्वारा डिलीवरी पार्टनर्स के अमूल्य योगदान के लिए उन्हें सम्मानित करती है, और उनके परिवारों में खुशियाँ फैलाती है।

ये पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में दिये गये हैं, जिनमें से हर एक डिलीवरी पार्टनर्स की प्रतिबद्धता और उपलब्धियों के लिए है।

'हीरोज इन रेड' पुरस्कार कार्यक्रम में पुरस्कार पाने वालों के परिवार की मौजूदगी में छह श्रेणियों में पुरस्कार दिये गये, जिनमें से प्रत्येक ने ज़ोमैटो के समर्पित डिलीवरी पार्टनर्स के असाधारण योगदान को सम्मानित किया।

'टॉप परफॉर्मर्स' पुरस्कार हर ज़ोन में सर्वोच्च 10 डिलीवरी पार्टनर्स को दिया गया। यह सबसे अधिक संख्या में ऑर्डर पहुँचाने की उनकी एफिशिएंसी को सम्मानित करता है। 'एवरीडे हीरोज' उन डिलीवरी पार्टनर्स को सम्मानित करता है, जो अपने दैनिक जीवन में व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करते हुए लचीलेपन और प्रतिबद्धता के साथ उत्कृष्ट सेवा देते हैं। 'मेड ए डिफरेंस' उन डिलीवरी पार्टनर्स को दिया गया, जिन्होंने ग्राहकों के जीवन में खुशी लायी या जरूरत के समय अपने साथी डिलीवरी पार्टनर्स की मदद की, जिससे उनकी करुणा व सपोर्ट प्रदर्शित होती है।

'इलेक्ट्रीफ़ाइंग पार्टनर' द्वारा ज़ोमैटो उन डिलीवरी पार्टनर्स को सम्मानित करता है, जिन्होंने सस्टेनेबल विधियों को बढ़ावा देते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों से सबसे ज़्यादा दूरी तय कर डिलीवरी प्रदान की। 'आयरन लेडीज' पुरस्कार उन महिला डिलीवरी पार्टनर्स को दिया गया, जिन्होंने खुशियां फैलाने, बाधाओं को तोड़ने और दूसरों को प्रेरणा देने के लिए सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। 'एजलेस अचीवर्स' 50 साल से ज़्यादा उम्र के डिलीवरी पार्टनर्स को दिया गया, जो अपनी बेजोड़ ऊर्जा और उत्साह के साथ उम्र की परिभाषा बदल रहे हैं, और सेवा प्रदान करने की अपनी तत्परता को प्रमाणित कर रहे हैं। ज़ोमैटो के सीईओ, फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी, राकेश रंजन ने कहा, 'हमारे संस्थान की नींव हमारे डिलीवरी पार्टनर हैं। अक्सर हमारे प्रतिबद्ध डिलीवरी पार्टनर्स की हृदयस्पर्शी कहानियाँ सामने आती हैं, जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी समाज को अपनी सेवा देने के लिए अपने कर्तव्य से बढ़कर काम करते हैं। ये पुरस्कार लोगों की मदद करने की उनकी तत्परता और उनकी असाधारण सेवा को सम्मानित करने का हमारा प्रयास हैं।' ज़ोमैटो अपने सभी डिलीवरी पार्टनर्स को एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी अपने डिलीवरी नेटवर्क में दयालुता की संस्कृति का विकास करते हुए पार्टनर्स की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग प्रशिक्षण एवं सपोर्ट प्रोग्राम्स के लिए करती रहेगी।'

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।